

सम्पूर्ण-संक्षिप्त-समर्थ

CURRENT AFFAIRS गुरु

UPSC/State PSC परीक्षा की तैयारी करने वाले हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए



26th AUGUST 2022



FOR DAILY FREE CURRENT AFFAIRS
Follow Our Youtube Channel

 Guru Deekshaa Hindi



INDEX

DAILY CURRENT AFFAIRS NOTES

26th August 2022

1. - विधायकों की अयोग्यता के बारे में:	3
(i) संविधान के अनुसार, एक व्यक्ति विधान परिषद (एमएलसी) या विधान सभा (एमएलए) में पद धारण करने के लिए अपात्र है यदि वे:	3
(ii) दलबदल विरोधी अधिनियम की अनुसूची 10 के अनुसार, एक व्यक्ति विधान सभा (एमएलए) के सदस्य या विधान परिषद (एमएलसी) के सदस्य के रूप में सेवा करने के लिए अपात्र है यदि:	3
(iii) लाभ का कार्यालय:	3
(iv) व्यवसाय लाभदायक है या नहीं यह निर्धारित करने के लिए दिशानिर्देश:	3
2. - पेगासस वायरस का विवरण:	4
(i) के बारे में:	4
(ii) लक्ष्य:	4
(iii) हाल की भारतीय घटनाएं:	4
(iv) विधान:	5
3. - ओबीसी के उप वर्गीकरण के बारे में:	6
(i) के बारे में:	6
(ii) इसका निम्नलिखित लाभ है:	6
(iii) पार्श्वभूमि:	6
(iv) उद्देश्य:	6
(v) संविधान के 102वें संशोधन के संबंध में:	6
(vi) ओबीसी उपवर्गीकरण जानकारी:	6
(vii) रोहिणी आयोग क्यों बनाया गया था?	7
(viii) रोहिणी आयोग के लिए सिफारिशें:	7
(ix) अब तक के निष्कर्ष:	7
(x) निष्कर्ष थे:	7



4. - विमान वाहक विक्रांत का विवरण:.....	8
(i) के बारे में:	8
(ii) महत्व:	8
(iii) भारतीय नौसेना की वर्तमान स्थिति:.....	8
(iv) कोविड-19 सुरक्षा में नौसेना की भागीदारी:.....	8
संपादकीय विश्लेषण	9
1. भारत के पार सीमा जल संघर्ष:.....	9
(i) पार्श्वभूमि:.....	9
(ii) भारत के पड़ोसियों के साथ जल विवाद:.....	9
(iii) भारत और चीन का जल संघर्ष:.....	9
(iv) भारत और बांग्लादेश के बीच जल विवाद:.....	10
(v) भारत और नेपाल के बीच जल विवाद:.....	10
(vi) भारत और पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर विवाद:.....	11
(vii) भूटान और भारत के बीच जल विवाद:.....	11
(viii) आगे बढ़ने का रास्ता:.....	12
2. भारत ब्रिटेन संबंध:	13
(i) भारत और ब्रिटेन के बीच संबंध इन पांच स्तंभों पर बने हैं:.....	13
(ii) भारत और ब्रिटेन के व्यापार और आर्थिक संबंध:	13
(iii) यूके को भारत के शीर्ष निर्यात हैं:	13
(iv) भारत में शीर्ष ब्रिटिश निर्यात इस प्रकार हैं:.....	13
(v) ब्रिटिश और भारतीय सांस्कृतिक समानताएं:.....	14
(vi) भारत और यूनाइटेड किंगडम का परमाणु सहयोग:.....	14
(vii) शैक्षिक कनेक्शन:.....	14
(viii) भारत और यूके रक्षा क्षेत्र में निम्नलिखित तरीके से सहयोग कर रहे हैं:	14
(ix) स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग:	14
(x) आगे बढ़ना/आगे बढ़ना:	15



1. - विधायकों की अयोग्यता के बारे में:

GS II

विषय→चुनाव संबंधित मुद्दे

संविधान के अनुसार, एक व्यक्ति विधान परिषद (एमएलसी) या विधान सभा (एमएलए) में पद धारण करने के लिए अपात्र है यदि वे:

- वह भारत सरकार, राज्य या राज्य द्वारा नामित किसी अन्य इकाई के साथ किसी भी आकर्षक स्थिति में है।
- कोई भी सक्षम न्यायालय किसी भी सदस्य को पागल घोषित कर सकता है।
- वह या तो दिवालिया है, दिवालिया है या उसके पास चार्जशीट है।
- वह भारत का नागरिक नहीं है।
- उन्होंने औपचारिक रूप से एक विदेशी सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ ली है या किसी अन्य राष्ट्र का नागरिक बनने का विकल्प चुना है।

दलबदल विरोधी अधिनियम की अनुसूची 10 के अनुसार, एक व्यक्ति विधान सभा (एमएलए) के सदस्य या विधान परिषद (एमएलसी) के सदस्य के रूप में सेवा करने के लिए अपात्र है यदि:

- एक निर्वाचित अधिकारी स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है।
- उनके राजनीतिक दल या ऐसा करने की शक्ति वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश की ऐसे सदन के निर्वाचित सदस्य द्वारा अवहेलना की जाती है जब वह मतदान करता है या मतदान से दूर रहता है।

- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत, एक व्यक्ति को विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में सेवा करने के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है यदि उन्हें अनैतिक चुनाव-संबंधी व्यवहार में भाग लेने के लिए जिम्मेदार माना जाता है।
- कोई भी व्यक्ति अपराध का दोषी है और धारा 8 (1), (2), और (3) के अनुसार जेल की सजा सुनाई गई है।

लाभ का कार्यालय:

- "लाभ का पद" शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है।
- हालाँकि, धारा 102 (1) और 191 (1), जो लाभ के पद की अवधारणा को व्यवहार में लाते हैं, ने संघीय और राज्य सरकार के पदों पर रहने वाले सांसदों पर प्रतिबंध स्थापित किए।

व्यवसाय लाभदायक है या नहीं यह निर्धारित करने के लिए दिशानिर्देश:

- यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई पद संवैधानिक अयोग्यता के लिए अतिसंवेदनशील है, चार व्यापक धारणाएँ उत्पन्न हुई हैं।
- क्या सरकार के पास कार्यालय के कर्तव्यों को नियुक्त करने, हटाने और पूरा करने की शक्ति है।
- भले ही रोजगार का भुगतान किसी भी तरह से किया जाए,
- क्या पद धारण करने वाले व्यक्ति के पास संरक्षण के माध्यम से प्रभावित करने की शक्ति है और क्या जिस संगठन में कार्यालय है, उसके पास सरकारी अधिकार है (धन जारी करना, भूमि आवंटित करना, लाइसेंस देना, आदि)।
- स्रोत→ हिन्दू



2. - पेगासस वायरस का विवरण:

लक्ष्य:

जीएस III

विषय → भारत की आंतरिक सुरक्षा

के बारे में:

- यह एक प्रकार का स्पाइवेयर है जो मैलवेयर की श्रेणी में आता है।
- इसका उद्देश्य गुप्त रूप से उपकरणों तक पहुंच बनाना, उपयोगकर्ता डेटा एकत्र करना और फिर उस डेटा को उस व्यक्ति को रिले करना है जो जासूसी करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा है।
- Pegasus को इजराइली व्यवसाय NSO Group द्वारा विकसित किया गया था, जिसे 2010 में बनाया गया था।
- पेगासस का पहला ज्ञात पुनरावृत्ति, जिसे शोधकर्ताओं ने 2016 में खोजा था, स्पीयर-फिशिंग के माध्यम से फोन को लक्षित किया, पाठ संदेशों या ईमेल में एक दुर्भावनापूर्ण लिंक पर क्लिक करने के लिए एक लक्ष्य को धोखा देने की तकनीक।
- लेकिन तब से एनएसओ की आक्रामक शक्तियां बढ़ गई हैं। तथाकथित "शून्य-क्लिक" हमले, जो फोन स्वामी की सहायता के बिना सफल होते हैं, पेगासस संक्रमण का कारण बन सकते हैं।
- ये आमतौर पर "शून्य-दिन" कमजोरियों, या ऑपरेटिंग सिस्टम की खामियों या मुद्दों का उपयोग करते हैं जिनके बारे में फोन निर्माता को अभी तक पता नहीं है और इसलिए वे ठीक नहीं कर पाए हैं।

- अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रचारक, पत्रकार और वकील एक इजरायली खुफिया एजेंसी द्वारा निरंकुश देशों को वितरित किए गए फोन स्पाइवेयर का लक्ष्य रहे हैं।
- सरकारी अधिकारियों, विपक्षी हस्तियों और भारतीय मंत्रियों को उन लोगों की सूची में शामिल किया गया है जिनके फोन को स्पाइवेयर द्वारा छेड़छाड़ की गई हो सकती है।
- 2019 में, व्हाट्सएप ने अमेरिकी अदालत में इजरायल के एनएसओ ग्रुप के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि फर्म मोबाइल उपकरणों पर मैलवेयर संक्रमण के माध्यम से सेवा के खिलाफ साइबर हमले शुरू कर रही है।

हाल की भारतीय घटनाएं:

- साइबर सुरक्षित भारत पहल 2018 में साइबर अपराध के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने और सभी सरकारी मंत्रालयों में फ्रंटलाइन आईटी कर्मचारियों और मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (सीआईएसओ) की क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र (एनसीसीसी) की स्थापना 2017 में आने वाले इंटरनेट ट्रैफिक और संचार मेटाडेटा की निगरानी के लिए की गई थी - प्रत्येक संचार के अंदर सूचना के छोटे-छोटे टुकड़े - वास्तविक समय में साइबर खतरों को देखने के लिए।
- 2017 में विकसित, साइबर स्वच्छता केंद्र प्लेटफॉर्म इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को वायरस और स्पाइवेयर से छुटकारा पाकर अपने कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को साफ करने में सक्षम बनाता है।



- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C): I4C को सरकार द्वारा अभी-अभी आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया है।
- भारत ने साइबर अपराध के लिए एक राष्ट्रव्यापी रिपोर्टिंग प्रणाली भी विकसित की है।
- प्राथमिक संगठन जो फिशिंग और हैकिंग जैसे साइबर सुरक्षा मुद्दों से निपटता है, CERT-IN (कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉंस टीम - इंडिया) है।

विधान:

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000
- 2019 का व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे संगठन:
- दूरसंचार और साइबर सुरक्षा के मुद्दों का विकास और मानकीकरण संयुक्त राष्ट्र के भीतर एक विशेष संगठन, अंतराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) से काफी प्रभावित है।
- राष्ट्रीय कानूनों में सामंजस्य स्थापित करके, खोजी तकनीकों को आगे बढ़ाते हुए, और अधिक अंतराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करते हुए, साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन इंटरनेट और कंप्यूटर अपराध (साइबर अपराध) से निपटने का प्रयास करता है। यह 1 जुलाई 2004 को लागू हुआ।
- भारत द्वारा इस समझौते की पुष्टि नहीं की गई है।
- स्रोत→ इंडियन एक्सप्रेस



3. - ओबीसी के उप वर्गीकरण के बारे में:

जीएस II

विषय→सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

के बारे में:

- केंद्रीय सूची के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) उप-वर्गीकरण आयोग की जांच का केंद्र बिंदु था।
- विस्तार 31 जुलाई, 2021 से 31 जनवरी, 2022 तक, अतिरिक्त छह महीनों के लिए प्रभावी है।

इसका निम्नलिखित लाभ है:

- "आयोग" कार्यकाल के प्रत्याशित विस्तार और अपने जनादेश के विस्तार के लिए कई हितधारकों के साथ बात करने के बाद ओबीसी के उप-वर्गीकरण के विषय पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रदान करने में सक्षम होगा।

पार्श्वभूमि:

- अक्टूबर 2017 में रोहिणी आयोग का गठन किया गया था।

उद्देश्य:

- यह देखने के लिए कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कैसे विभाजित हैं और उनके बीच उनके लाभों को उचित रूप से कैसे वितरित किया जाए

- विस्तार का औचित्य: सुप्रीम कोर्ट ने अपने 5 मई के फैसले की सुनवाई के लिए संघीय सरकार की याचिका को ठुकरा दिया, जिसमें कहा गया था कि संविधान में 102 वां संशोधन सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) को परिभाषित करने के लिए राज्यों की शक्ति को छीन लेता है। क्षेत्र।

संविधान के 102वें संशोधन के संबंध में:

- परिणामस्वरूप राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को कानूनी दर्जा दिया गया है।
- इसके अतिरिक्त, इसमें अनुच्छेद 338B शामिल है, जो आयोग की संरचना, कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है, साथ ही अनुच्छेद 342A, जो राष्ट्रपति को SEBC के रूप में एक वर्ग को नामित करने का अधिकार देता है और संसद को केंद्रीय SEBC सूची में संशोधन करने का अधिकार देता है। .

ओबीसी उपवर्गीकरण जानकारी:

- संघीय सरकार ओबीसी के लिए रोजगार और शिक्षा दोनों में 27% आरक्षण प्रदान करती है।
- सुप्रीम कोर्ट की भागीदारी: पिछले साल सितंबर में, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आरक्षण के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उप-वर्गीकरण पर कानूनी बहस फिर से खोल दी।
- केवल अमीर समुदायों को ही आरक्षण देने की अनुमति है: केंद्रीय सूची में शामिल 2,600 से अधिक ओबीसी में से, तर्क यह है कि केवल कुछ अमीर समूहों को 27 प्रतिशत कोटा का एक बड़ा हिस्सा मिला है।



रोहिणी आयोग क्यों बनाया गया था?

- 2 अक्टूबर, 2017 को ओबीसी के उप-वर्गीकरण को देखने के लिए रोहिणी आयोग का गठन किया गया था।
- रिपोर्ट को समाप्त करने के लिए शुरू में 12 सप्ताह का समय था, लेकिन तब से कई एक्सटेंशन जारी किए गए हैं; सबसे हाल का समय 11 नवंबर तक था।
- आयोग के अन्य सदस्य सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज के निदेशक जितेंद्र बजाज हैं।
- रोहिणी आयोग बनने से पहले, केंद्र ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा दिया था।

रोहिणी आयोग के लिए सिफारिशें:

- ओबीसी की बड़ी श्रेणी बनाने वाली जातियों या समूहों और कोटा लाभों के आवंटन में केंद्रीय सूची में शामिल वर्गों के बीच असमानता की डिग्री निर्धारित करने के लिए;
- ओबीसी की केंद्रीय सूची में उपयुक्त जातियों, समुदायों, उप-जातियों या समानार्थक शब्दों का पता लगाना और उन्हें उचित उप-श्रेणियों में रखना; और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए ऐसे ओबीसी के भीतर उप-वर्गीकरण के लिए तंत्र, मानदंड, मानदंड और पैरामीटर तैयार करना।
- ओबीसी की केंद्रीय सूची में प्रत्येक प्रविष्टि की पुनरावृत्ति, अस्पष्टता, विरोधाभास और प्रतिलेखन या वर्तनी की त्रुटियों के लिए जाँच करनी चाहिए, और उन्हें समाप्त करने की सलाह देनी चाहिए।

अब तक के निष्कर्ष:

- पिछले तीन वर्षों में विश्वविद्यालयों, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम और एम्स सहित केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में ओबीसी प्रवेश की भी आयोग द्वारा 2018 में जांच की गई थी। कुल मिलाकर, ओबीसी कोटा के तहत पिछले 1.3 लाख सरकारी पदों को भरा गया था। पांच साल भी देखे गए।

निष्कर्ष थे:

- सभी ओबीसी उपजातियों में से केवल 25% को सभी नौकरियों और शैक्षिक सीटों का 97% प्राप्त हुआ; दस ओबीसी समुदायों को इनमें से 24.5% नौकरियां और सीटें मिलीं; 983 ओबीसी समुदायों, या कुल का 37%, नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है; और 994 ओबीसी उपजातियों का भर्ती और प्रवेश में केवल 2.68 प्रतिशत का संयुक्त प्रतिनिधित्व है।
- इस अध्ययन में केवल 42 केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभाग शामिल हैं।
- चूंकि ओबीसी उम्मीदवारों को बहुत सारे पदों के लिए "एनएफएस" के रूप में चिह्नित किया गया था, जो ओबीसी के लिए थे, इसलिए उतने आवेदक नहीं थे जितने होने चाहिए थे (कोई भी उपयुक्त नहीं पाया गया)।
- **स्रोत→ हिन्दू**



4. - विमान वाहक विक्रांत का विवरण:

प्रीलिम्स विशिष्ट विषय

के बारे में:

- पोत का नाम, विक्रांत, नौसेना के पहले सेवामुक्त वाहक से लिया गया है।
- इसमें कुल 30 विमान होंगे, जिनमें स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर, मिग-29के लड़ाकू जेट, कामोव-31 हवाई पूर्व चेतावनी हेलीकॉप्टर और जल्द ही शामिल किए जाने वाले एमएच-60आर बहु-भूमिका हेलीकॉप्टर शामिल हैं।
- इसके 30 समुद्री मील की शीर्ष गति तक पहुंचने की उम्मीद है और यह चार गैस टर्बाइन (लगभग 55 किलोमीटर प्रति घंटे) द्वारा संचालित है। इसमें 7,500 नॉटिकल मील रेंज और 18 नॉट स्पीड (32 किलोमीटर प्रति घंटे) है।
- MFSTAR और RAN-40L 3D रडार सेंसर के रूप में उपयोग किए जाते हैं, और जहाज से चलने वाले हथियारों में AK-630 और बराक LR SAM शामिल हैं। जहाज पर एक शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट स्थापित किया गया है।
- इसके दो रनवे हैं और विमान संचालन को नियंत्रित करने के लिए "शॉर्ट टेक ऑफ लेकिन अरेस्ट रिकवरी" पद्धति का उपयोग करता है।

महत्व:

- विमानवाहक पोत की युद्ध क्षमता, रेंज और चपलता भारत की रक्षा को महत्वपूर्ण नए उपकरण देगी और राष्ट्र के समुद्री हितों की सेवा करेगी।

- यह लंबी दूरी तक हवाई शक्ति को प्रोजेक्ट करने की अपनी क्षमता के कारण हवाई अवरोध, सतह-विरोधी युद्ध, आक्रामक और रक्षात्मक काउंटर-एयर, हवाई पनडुब्बी रोधी युद्ध और हवाई पूर्व चेतावनी के लिए एक बेहतर सैन्य क्षमता प्रदान करेगा।

भारतीय नौसेना की वर्तमान स्थिति:

- समुद्री क्षमता परिप्रेक्ष्य योजना के अनुसार, भारत के पास 2027 तक लगभग 200 जहाज होने चाहिए, लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है।
- हालांकि, वित्तपोषण के बजाय, प्रक्रियात्मक देरी या विशेष रूप से स्वयं द्वारा लगाए गए प्रतिबंध मुख्य कारण हैं।
- नौसेना अपने सोनार और रडार की आधुनिकता सुनिश्चित करती है। कई जहाजों पर, स्थानीय सामग्री का एक बड़ा हिस्सा भी मौजूद है।

कोविड-19 सुरक्षा में नौसेना की भागीदारी:

- ऑपरेशन समुद्र सेतु- I का उद्देश्य उन भारतीय नागरिकों को वापस लाना है, जिन्होंने कोरोनावायरस के यात्रा प्रतिबंधों के बावजूद विदेश यात्रा की है।
- ऑपरेशन समुद्र सेतु-द्वितीय भारतीय नौसेना द्वारा भारत में ऑक्सीजन युक्त कंटेनरों के परिवहन के लिए शुरू किया गया था।

- स्रोत→ इंडियन एक्सप्रेस



संपादकीय विश्लेषण

1. भारत के पार सीमा जल संघर्ष:

पार्श्वभूमि:

- यह देखते हुए कि इसके पास दुनिया के जल संसाधनों का लगभग 4% है, भारत के पास पर्याप्त जल आपूर्ति होनी चाहिए थी। लेकिन 2011 में, भारत को पानी की कमी का अनुभव होने लगा।
- नीति आयोग के शोध के अनुसार, जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत अब 122 देशों में 120वें स्थान पर है।
- यह चीन और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से अधिक भूजल का उपयोग करता है (वैश्विक कुल का 24%)।
- संयुक्त राष्ट्र की भविष्यवाणियों के अनुसार, भारत की पानी की मांग 2030 तक लगभग 740 बिलियन क्यूबिक मीटर से बढ़कर लगभग 1.5 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर होने की उम्मीद है। (2010 के लिए अनुमानित)।
- अपने पड़ोसियों के साथ भारत के जल विवादों और भारत में अंतरराज्यीय नदी जल की समस्याओं से स्थिति काफी खराब हो गई है।

भारत के पड़ोसियों के साथ जल विवाद:

- पानी का मुद्दा दक्षिण एशिया के अधिकांश हिस्सों में राजनीतिक रूप से विभाजनकारी बना हुआ है। इस क्षेत्र में जिस तेजी से विकास हो रहा है, वह इस क्षेत्र की पहले से ही गंभीर पानी की कमी और कृषि समस्याओं को बढ़ा देगा।
- अत्यधिक भूजल निकासी एक महत्वपूर्ण समस्या है, क्योंकि बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान में 23 मिलियन से अधिक पंप उपयोग में हैं।

- इसके अलावा, भारत-गंगा के मैदान में भूजल 60% से अधिक लवणयुक्त और आर्सेनिक दूषित है।
- इन कारकों को जलवायु परिवर्तन के परिणामों में जोड़ें, जो ब्रह्मपुत्र बेसिन की जल आपूर्ति और बदलते जल प्रवाह पैटर्न को बदल रहे हैं।
- ऐसी परिस्थितियों में, बिजली की बढ़ती मांग और स्थिर जल स्तर भविष्य में द्विपक्षीय जल-साझाकरण समझौतों के सुधार के लिए उत्प्रेरक का काम कर सकते हैं।

भारत और चीन का जल संघर्ष:

- गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों ही चीनी ग्लेशियरों से अपना पानी प्राप्त करते हैं। चीन बुनियादी ढांचे का निर्माण करके पानी को नीचे की ओर बहने से रोकने की अच्छी स्थिति में है क्योंकि यह एक अपस्ट्रीम रिपेरियन क्षेत्र है।
- अतीत में अपनी जलविद्युत परियोजनाओं के बारे में जानकारी छिपाने की चीन की प्रवृत्ति के कारण, दोनों पड़ोसियों के बीच विश्वास की कमी है।
- संचार और रणनीतिक विश्वास में सुधार के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के बावजूद, ब्रह्मपुत्र के साथ बांध बनाने और पानी साझा करने की चीन की आकांक्षाओं के कारण दो पड़ोसियों (चीन में यारलुंग जंगबो के रूप में जाना जाता है) के बीच संघर्ष होता है।
- बांग्लादेश और भारत जैसे निचले तटवर्ती देश कृषि के लिए ब्रह्मपुत्र के पानी पर निर्भर हैं।
- चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र पर चार और बांध बनाएगा। भारत और बांग्लादेश दोनों इस बात से चिंतित हैं कि बीजिंग इन बांधों का इस्तेमाल राजनीतिक संकट की स्थिति में पानी को मोड़ने या स्टोर करने के लिए कर सकता है।



- दूसरी ओर, भारत ने शुष्क मौसम के दौरान प्रवाह का उपयोग करने के लिए ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी, तीस्ता नदी पर बांध बनाए हैं।

भारत और बांग्लादेश के बीच जल विवाद:

- भारत और बांग्लादेश तीस्ता नदी साझा करते हैं, जो हिमालय से निकलती है और असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना में शामिल होने से पहले सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। शायद दो मित्र पड़ोसियों के बीच सबसे विवादास्पद मुद्दा यह है।
- नदी सैकड़ों हजारों लोगों के जीवन को नियंत्रित करती है, सिक्किम के बाढ़ के मैदानों को लगभग पूरी तरह से भर देती है, और बांग्लादेश के 2,800 वर्ग किलोमीटर को बहा देती है।
- पश्चिम बंगाल तीस्ता नदी पर भी बहुत महत्व रखता है, जिसे छह उत्तरी बंगाली जिलों की जीवन रेखा माना जाता है।
- बांग्लादेश ने भारत से अपनी साझा सीमा के करीब फरक्का बैराज में सतही जल साझा करने के प्रयास में 1996 की गंगा जल संधि की तर्ज पर तीस्ता जल के "समान" वितरण के लिए कहा है।
- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की 2015 की ढाका यात्रा ने आशावाद को जन्म दिया कि एक निष्पक्ष और समान जल बंटवारा समझौते के आसपास के मुद्दों को दूर किया जाएगा।
- हालाँकि, तीस्ता अभी भी एक कार्य प्रगति पर है क्योंकि भारत में अंतरराष्ट्रीय समझौते अलग-अलग राज्यों से काफी प्रभावित हैं। इस संरचना द्वारा नीतियां बनाना कभी-कभी अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया जाता है। उदाहरण के लिए, सौदे के प्रमुख पक्षों में से एक, पश्चिम बंगाल ने अभी तक अपनी सहमति नहीं दी है।

भारत और नेपाल के बीच जल विवाद:

- कोसी, गंडकी, करनाली, या महाकाली जैसी महत्वपूर्ण नदियों के संबंध में नेपाल और भारत के बीच जल सहयोग पर समझौते हुए हैं। ये समझौते अक्सर बड़े आकार की सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए होते हैं जिनमें बांधों या बैराजों के निर्माण की आवश्यकता होती है।
- कोसी बैराज को छोड़कर कोई भी परियोजना पूरी नहीं हुई है। छोटी नदियों की भी अनदेखी की जाती है।
- जल अधिकारों के मुद्दों को 1954 के बाद से हल नहीं किया गया है, जब भारत और नेपाल ने कोसी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जब दोनों देशों के बीच बातचीत बंद हो गई थी।
- कोसी क्षेत्र में बाढ़ के परिणामस्वरूप इस व्यवस्था के बारे में कई तर्क दिए गए हैं।
- कोसी बांध मुआवजे के मुद्दे पर भी भारत और नेपाल के बीच विवाद होते रहे हैं।
- इसके अलावा, नेपाल ने निर्माण को अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन माना।
- कोसी नदी का उच्च स्तर का अवसादन एक समस्या है, और तटबंध इसे धीमा करने में विफल रहे हैं।
- भंडारण टैंक बनाने का एकमात्र अन्य विकल्प है, जो नेपाल की मदद के बिना नहीं किया जा सकता है।
- भारत और नेपाल की ऐतिहासिक रूप से सुगौली संधि की विभिन्न व्याख्याएं हैं, जिस पर 1816 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और नेपाल में महा काली नदी के साथ सीमा की स्थापना की थी।
- नदी का स्रोत भारत और नेपाल में अलग-अलग है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह किस धारा से आती है।



- भारत और नेपाल के बीच संघर्ष, जो पहली नज़र में महत्वहीन लगता है, विवादित क्षेत्र की चीन-भारतीय सीमा से निकटता के कारण सामरिक महत्व प्राप्त करता है।

भारत और पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर विवाद:

- बंटवारे के बाद से कई जल संघर्षों को लेकर भारत और पाकिस्तान एक-दूसरे के साथ हैं।
- प्रारंभिक राष्ट्रीय नेताओं ने अपनी अस्थिर सीमा को विभाजित करने वाले महासागरों के नियंत्रण के लिए इस खूनी लड़ाई का अनुमान लगाया।
- नतीजतन, लंबी बातचीत और सतर्क सौदेबाजी के बाद, दोनों देशों ने 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसने क्षेत्र की नदियों के सटीक विभाजन को निर्दिष्ट किया।
- इस समझौते ने पाकिस्तान को पश्चिम में सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों पर नियंत्रण दिया, जबकि भारत को पूर्व में ब्यास, रावी और सतलुज नदियों पर नियंत्रण प्रदान किया।
- स्वतंत्रता के बाद दो शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों के बीच तीन संघर्षों के बाद सिंधु जल संधि को सर्वसम्मति से विजय के रूप में स्वागत किया गया है।
- 1960 के दशक से पाकिस्तान की स्थिति में काफी बदलाव आया है, और देश में अब पानी खत्म होने का खतरा है।
- चूंकि भारत पाकिस्तान की सभी नदियों का स्रोत या नाली है, इसलिए यह केवल समझ में आता है कि भारत का इस बात पर अधिक प्रभाव पड़ेगा कि ये नदियाँ पाकिस्तान से कैसे निकलती हैं।
- भारत सरकार के पास पश्चिमी नदियों पर 40 से अधिक परियोजनाएँ हैं जो या तो पूर्ण हैं या प्रस्ताव चरण में हैं।

पश्चिमी नदियों में इस तरह की गतिविधियों के जारी रहने पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है।

- दूसरी ओर, भारत इस बात से इनकार करता रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये आरोप सही हैं और विज्ञान द्वारा समर्थित नहीं हैं।
- पाकिस्तान ने 2005 में चिनाब नदी पर भारत की 450 मेगावाट की बगलिहार बांध परियोजना के विरोध में विश्व बैंक के समक्ष असफल तर्क दिया।
- जम्मू और कश्मीर में 330 मेगावाट की किशनगंगा परियोजना 2011 में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय (आईसीए) के समक्ष दोनों देशों के तर्कों का विषय थी।
- भारत में चिनाब नदी के किनारे जलविद्युत बांधों का निर्माण सबसे मौजूदा विवाद का विषय है। पाकिस्तान का मानना है कि ये कार्रवाइयाँ कन्वेंशन का उल्लंघन करती हैं और इससे उसकी जलापूर्ति पर असर पड़ेगा।

भूटान और भारत के बीच जल विवाद:

- भारत और भूटान के बीच जलविद्युत ऊर्जा सहयोग 50 साल से भी पहले स्थापित किया गया था।
- ताला, चुखा और कुरिचु कुछ मामूली जलविद्युत परियोजनाएँ थीं जिन्हें समझौते के परिणामस्वरूप विकसित किया गया था।
- भूटान के पास 30,000 मेगावाट पनबिजली पैदा करने की क्षमता है।
- 2006 में, दोनों देशों के बीच 35 साल के बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे भारत भूटान से 5000 मेगावाट जलविद्युत का उत्पादन और खरीद कर सका, जिसकी क्षमता 2008 में बढ़कर 10,000 मेगावाट हो गई।



- हालांकि, देश पर उनके संभावित दीर्घकालिक प्रभावों के कारण, भूटानी निवासियों ने ऐसी परियोजनाओं का विरोध किया।
- उदाहरण के लिए, यदि भूटान कभी भी भंडारण परियोजनाओं का निर्माण करने का निर्णय लेता है, तो भारत के साथ मुद्दे और खराब हो सकते हैं और अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं।
- भूटान का आंतरिक मुद्दा पानी की पहुंच है।

प्रबंधन और नेविगेशन, बिजली उत्पादन और पानी की गुणवत्ता पर सहयोग करना।

- सफल होने पर, औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय मंच अंततः सरकारों को सहयोग के अनौपचारिक रूपों पर विचार करने के लिए राजी कर सकते हैं, जो (कुछ सीमाओं के बावजूद) उन्हें विश्वास-निर्माण को आगे बढ़ाने, संघर्षों को निपटाने और साझा जलमार्गों का प्रबंधन करने में मदद कर सकते हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता:

- पानी के उपयोग और बंटवारे पर नियमित रूप से कम ध्यान दिया जाता है, अधिक गंभीर सीमा या सुरक्षा मुद्दों के साथ, या केवल प्राकृतिक आपदा होने पर ही संबोधित किया जाता है। हालांकि, किसी देश की सुरक्षा और समृद्धि जल राजनीति से काफी प्रभावित होती है।
- इस तथ्य के बावजूद कि यह सीमा-पार मुद्दा उनकी राष्ट्रीय विकास नीतियों के केंद्र में है, जिन देशों के पास सीमा-पार जल बंटवारा समझौते हैं, उन्हें इसका गहन अध्ययन करने और इसे समझने की आवश्यकता है।
- अन्य तटवर्ती देशों के बीच कठिन और समझौता न करने वाली भू-राजनीतिक स्थिति, दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप में नदियों के जटिल अभिविन्यास के साथ, जो इस क्षेत्र के कुछ देशों से होकर गुजरती है, इस क्षेत्र में पानी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है।
- इन समझौतों की कुछ महत्वपूर्ण चर्चाओं के साथ-साथ क्षेत्रीय संगठनों की सक्रिय भागीदारी और शेयरधारकों के बीच आपसी समझ के माध्यम से, इन बाधाओं को अनुभव के संदर्भ में दूर किया जा सकता है।
- दक्षिण एशिया में हाइड्रोडिप्लोमेसी जल्द ही कम संवेदनशील विषयों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है जैसे कि पूर्वानुमान डेटा का आदान-प्रदान करके बाढ़ का



2. भारत ब्रिटेन संबंध:

भारत में शीर्ष ब्रिटिश निर्यात इस प्रकार हैं:

भारत और ब्रिटेन के बीच संबंध इन पांच स्तंभों पर बने हैं:

- व्यापार और अर्थव्यवस्था
- लोगों को लोगों से जोड़ना
- स्वास्थ्य
- बचाव
- आपसी सुरक्षा

भारत और ब्रिटेन के व्यापार और आर्थिक संबंध:

- यूके में दूसरा सबसे बड़ा निवेशक भारत से है। यूके भारत का तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है, भले ही वह देश का 18वां सबसे बड़ा वाणिज्यिक भागीदार है।
- संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति (जेटको), जो सीमा पार निवेश को प्रोत्साहित करना चाहती है, की स्थापना 2005 में नई दिल्ली में हुई थी।

यूके को भारत के शीर्ष निर्यात हैं:

- तैयार वस्त्र और वस्त्र, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पाद, परिवहन उपकरण और पुर्जे, मसाले, धातु, मशीनों और उपकरणों के निर्माता, साथ ही निर्मित सामान, फार्मास्यूटिकल्स और समुद्री उत्पाद।

- रत्न, दोनों कीमती और अर्ध-कीमती, अयस्क, स्क्रैप धातु, इंजीनियरिंग आइटम, गैर-इलेक्ट्रॉनिक पेशेवर उपकरण, अलौह धातु, रसायन और उपकरण।
- सेवा क्षेत्र में, यूके आईटी सेवाओं के लिए यूरोप में भारत का सबसे बड़ा बाजार है।
- यूके से एफडीआई को आकर्षित करने वाले शीर्ष क्षेत्र पेट्रोलियम, बंदरगाह, सेवाएं, सड़कें और राजमार्ग और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं।
- यूके में अर्थव्यवस्था और कारोबारी माहौल भारतीय बहुराष्ट्रीय व्यवसायों के विकास से काफी प्रभावित हैं।
- भारत और ब्रिटेन के बीच वस्तुओं और सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार में पिछले दस वर्षों में वृद्धि हुई है।
- रोड मैप के अनुसार, 2021 में एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- यूके नर्सिंग की संभावनाओं को बढ़ावा देगा, भारतीय नाविकों की योग्यता को मान्यता देगा और अतिरिक्त भारतीय खिलाड़ियों के लिए मत्स्य उद्योग को खोलेगा। यह इस योजना के सामाजिक सुरक्षा समझौते खंड पर एक सहकारी वार्ता में भी शामिल होगा।
- भारत ने पारस्परिक कानूनी सेवाओं के उद्घाटन की दिशा में काम करने के लिए यूके के समझौते के बदले में फल, चिकित्सा आपूर्ति और मास्टर डिग्री की पारस्परिक मान्यता के लिए यूके के अनुरोधों का अनुपालन किया है।



ब्रिटिश और भारतीय सांस्कृतिक समानताएं:

- भारत और यूके ने जुलाई 2010 में सांस्कृतिक सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेहरू केंद्र (टीएनसी), 1992 में लंदन में स्थापित, यूके में भारत की सांस्कृतिक आउटरीच पहल का उच्चायोग है।

भारत और यूनाइटेड किंगडम का परमाणु सहयोग:

- दोनों देशों ने परमाणु व्यापार सहित और दोनों देशों के वैज्ञानिक संस्थानों के बीच परमाणु क्षेत्र में सहयोग का विस्तार और सुव्यवस्थित करने के लिए 2010 में असैन्य परमाणु सहयोग घोषणा पर हस्ताक्षर किए।
- संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं और तकनीकी, वैज्ञानिक, वित्तीय और नीतिगत क्षमताओं को साझा करने के उपायों सहित ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर सहयोग के व्यापक पैकेज के हिस्से के रूप में 2015 में यूके और भारत के प्रमुख नेताओं द्वारा एक परमाणु साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

शैक्षिक कनेक्शन:

- 38,000 से अधिक विद्यार्थियों के साथ भारत ब्रिटेन में विदेशी छात्रों का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। 2005 में, यूके-इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव (UKIERI) को अनुसंधान, उच्च शिक्षा, पेशेवर और तकनीकी कौशल और स्कूलों पर ध्यान देने के साथ शुरू किया गया था।
- 2016 को यूके-इंडिया ईयर ऑफ एजुकेशन, रिसर्च और इनोवेशन के रूप में नामित किया गया है।

भारत और यूके रक्षा क्षेत्र में निम्नलिखित तरीके से सहयोग कर रहे हैं:

- तीनों सेवाओं के प्रत्येक स्तर पर, अक्सर संयुक्त अभ्यास और उनके बीच पर्याप्त बातचीत होती है।
- दो प्रमुख नेताओं, मोदी और जॉनसन ने सहयोग को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है और यूके-भारत रक्षा गठबंधन के लिए एक सामान्य दृष्टिकोण रखा है।
- भारत और यूके ने समुद्री सूचना साझाकरण पर नए समझौतों और एक महत्वाकांक्षी अभ्यास योजना पर भी सहमति व्यक्त की, जिसमें संयुक्त त्रिपक्षीय अभ्यास शामिल हैं, साथ ही यूके को गुडगांव में भारत के सूचना संलयन केंद्र में शामिल होने का अनुरोध करने के अलावा।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग:

- स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छे के लिए वैश्विक बल के रूप में, यूके और भारत वैश्विक स्वास्थ्य में सबसे अधिक दबाव वाले मुद्दों को संबोधित करने, जीवन बचाने और स्वास्थ्य और भलाई में सुधार करने के लिए सहयोग करेंगे।
- भारत-यूनाइटेड किंगडम स्वास्थ्य साझेदारी का उद्देश्य नैदानिक शिक्षा, स्वास्थ्य कार्यकर्ता गतिशीलता और डिजिटल स्वास्थ्य पर सहयोग में वृद्धि के माध्यम से वैश्विक स्वास्थ्य और महामारी प्रतिरोध की सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही, यह स्वस्थ समाजों को आगे बढ़ाने और रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) के खिलाफ संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाने का प्रयास करता है।



आगे बढ़ना/आगे बढ़ना:

- 2030 का विजन नागरिकों के जीवन और आजीविका में सुधार, रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और भारत-यूके को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में दुनिया भर में अग्रणी के रूप में स्थापित करने के लिए व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को बहाल करने की दिशा में सही दिशा में एक कदम है।
- दुनिया की शीर्ष दो अर्थव्यवस्थाएं, भारत और यूके दोनों ही विनिर्माण, नवाचार, अनुसंधान, शिक्षा, अंतरिक्ष, रक्षा, हरित प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा सहित उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला में असाधारण उपलब्धियों के साथ संपन्न लोकतंत्र हैं। विषयों के लाभ के लिए इस संबंध को भुनाने के लिए, अधिक सहयोग की कोशिश की जानी चाहिए।
- आगामी सहयोग में बाधाओं की संभावना को कम करने के लिए सामूहिक रूप से रखे गए ऐतिहासिक सामान को भी संभाला जाना चाहिए।

GURU DEEKSHAA IAS

Guru Deekshaa IAS is happy to announce first ever kannada current affairs magazine for kannada medium aspirants of Karnataka. The three important thumb rules for any competitive exam are



Vijay Kumar G

Founder and Director
Guru Deekshaa IAS

- ✍ First-NCERT/STATE syllabus books which helps to develop your understanding on the subjects
- ✍ Second-Daily current affairs helped to build your further understanding of the events related to your examination, Apart from knowledge it build the personality of an individual which brings in confidence to face any examination.
- ✍ Third-Practice previous year question papers and mock test available in the market to train your mind as per the requirement of the examination.

Thousand miles of journey starts with single step, We at Guru Deekshaa have taken this first step towards empowering you to prepare for civil for services. Now its your turn to start preparation and achieve your dream of becoming IAS/IPS.

CALL US FOR MORE DETAILS

 **76 76 74 98 77**

JOIN OFFICIAL TELEGRAM FOR MATERIAL AND UPDATES

 **@GURU_DEEKSHAAIAS**



FOLLOW OUR INSTAGRAM FOR DAILY UPDATES

 **GURUDEEKSHAA**

